3 चेतना पाटिल का एक और कारनामा

5 सलमान खुर्शीद लेखक और कानून शिक्षक

6 ऑपरेशन सिंदूर; अब आजाद है बलूचिस्तान

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 02 प्रति सोमवार, 19 मई 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

देश की बेटी और सेना की शान पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह पर आखिर कब होगी कड़ी कार्रवाई?

■ पूर्व CM की पत्नी और छात्राओं के साथ अभद्रता कर चुके मंत्री कब होंगे बर्खास्त?

कवर स्टोरी
-विजया पाठक
एडिटर

मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने देश के गौरव के साथ अखण्डता और एकता पर वार किया है। उन्होंने ना सिर्फ बीजेपी को बल्कि भारतीय फौज को भी अपमानित किया है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भारतीय संस्कृति को मिट्टी में मिलाने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री पर कार्रवाई कर देश के सामने एक मिसाल पेश करे। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने की कोशिश करने वाले प्रदेश के मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह की कर्नल सौफिया कुरैशी पर की गई अभद्र टिप्पणी ने पूरे महिला समाज को शर्मसार कर दिया है। शाह के इस बयान ने न सिर्फ समाज के महिला वर्ग की

अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया है बल्कि उन्होंने देश की सीमा पर तैनात रहने वाली उन लाखों महिलाओं और बेटियों पर अभद्र टिप्पणी की है।

विजय शाह की इस टिप्पणी ने जहां भारतीय जनता पार्टी की महिला सम्मान की संस्कृति को तार-तार कर दिया है बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के महिला सैनिकों के सम्मान और वीरता के लिए दिये गये उस सलाम को भी मिट्टी में मिला दिया है जो उन्होंने दो दिन पहले राष्ट्र के संबोधन के नाम पर दी थी। समझने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचारी और दुराचारी मंत्री विजय शाह के दिमाग में गंदगी के अलावा क्या कुछ नहीं है। यह पहला अवसर नहीं है जब शाह ने इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दिया हो इससे पहले भी विजय शाह झुठी पब्लिसिटी पाने के लिए फज़लतू के बयान देते रहे हैं।(शेष पेज 2 पर)

मुख्यमंत्री साय ने आत्म समर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से पीड़ितों को जारी की प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के लोगों को प्रधानमंत्री आवास की नई सौगात दी है। मुख्यमंत्री साय ने आत्म समर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित 2500 परिवारों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पहली किस्त की राशि अंतरित की। उन्होंने मंत्रालय में वर्चुअली आयोजित कार्यक्रम में आवास निर्माण की पहली किस्त प्रति परिवार 40-40 हजार रुपए के मान से कुल दस करोड़ रुपए हितग्राहियों के खातों में अंतरित किए। छत्तीसगढ़ के विशेष आग्रह पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य के आत्म समर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए 15 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं।

आत्मीयता से बातकर उनका हाल-चाल पूछा

साय ने नक्सल प्रभावित दूरस्थ वनांचलों के लिए स्वीकृत इस विशेष परियोजना के हितग्राहियों की हौसला अफजाई करते हुए अच्छा मकान बनाने के लिए प्रेरित किया। (शेष पेज 2 पर)

कमलनाथ मुख्यमंत्री होते तो आज किसानों का कर्जा माफ हो जाता

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां की 70 फीसदी आबादी किसानी पर निर्भर है। इतनी बड़ी आबादी की आजीविका कृषि से चलती है। यही वजह रही कि 2018 में प्रदेश में आयी कमलनाथ की सरकार ने किसानों के हितों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जानते थे कि किसान ही प्रदेश के विकास की रीढ़ हैं। यदि किसान खुशहाल होंगे तो प्रदेश का हर नागरिक खुशहाल होगा। वो समझते थे कि किसानों की खुशहाली की सबसे बड़ी बाधा कर्जा थी। प्रदेश का हर किसान लाखों रूपये का कर्जदार था और अभी भी है। इस बाधा को दूर करने के लिए कमलनाथ ने पहली मीटिंग में ही किसानों की कर्जामाफी पर साईन किये। प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था के आधार स्तंभ किसानों को राहत देने के एक बड़े फैसले के साथ 05 जनवरी 2019 को नए

मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के किसानों के ऋण माफ करने का फैसला हुआ। देश में अब तक के इतिहास में किसी राज्य द्वारा किसानों के हित में लिया गया संभवतः ये पहला बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय था। (शेष पेज 2 पर)

कांग्रेस का जयचंद भूपेश बघेल: कई गंभीर अपराधों और घोटालों में संलिप्तता के बावजूद गिरफ्तारी नही, जॉच एजेंसियां पसोपेश में

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ के कई बड़े घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ नामदर्ज एफआईआर के बावजूद गिरफ्तार न होने से जनता हैरान है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान अपने भाषणों में साफ किया था कि राज्य में बीजेपी और केन्द्र में एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद छत्तीसगढ़ के घोटालेबाज नेताओं की खैर नही। चुन-चुनकर हिसाब लिया जायेगा। जो लूटा है वह लौटाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे जोशीले भाषण के बाद भ्रष्टाचार की मार झेल रही एक बड़ी आबादी बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका था। लेकिन केन्द्र और राज्य में बीजेपी के सत्ता में आने के बावजूद बघेल के गिरफ्तारी को लेकर संसय बना हुआ है। सीबीआई, ईडी, आईटी और ईओडब्ल्यू बघेल के खिलाफ कई बड़े घोटालों के लेकर जांच में जुटी है। जांच का सिलसिला करीब तीन सालों से बदस्तूर जारी है। (शेष पेज 7 पर)

देश की बेटी और सेना की शान पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह पर आखिर कब होगी कड़ी कार्रवाई?

(पेज 1 से जारी)

देश और प्रदेश की बेटी पर उठाया सवाल

विजय शाह ने इंदौर जिले के मानपुर क्षेत्र के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा पहले तो पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा, हर झोपड़ी और हर खोपड़ी में हलमा होना चाहिए, हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे हैं, समाज के लिए जान लगा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वह कटे-पिटे लोगों को, हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। आतंकवादियों ने कपड़े उतार-उतारकर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी-तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर भेजा। मोदी जी कपड़े उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा, कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारी समाज की बहन आकर के पाले खोल के छोड़ेगी।

डैमेज कंट्रोल की कोशिश न करे भाजपा बल्कि इस्तीफा ले

देश की बेटियों पर इस तरह के अभद्र किस्म की टिप्पणी करने वाला यह नालायक मंत्री विजय शाह को मोहन सरकार को तत्काल प्रभाव से कैबिनेट से बाहर कर देना चाहिए। यही नहीं राष्ट्रीय महिला आयोग को एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग को विजय शाह का विधायक पद समाप्त करने की सिफारिश करना चाहिए। कुल मिलाकर डॉ. मोहन यादव से लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक हर किसी को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और विजय शाह की राजनीतिक यात्रा पर तत्काल प्रभाव से ब्रेक लगाना चाहिए। क्योंकि यह समय डेमेज कंट्रोल का नहीं है बल्कि यह समय फैसला लेने का है अगर भाजपा, सत्ता और संगठन शाह के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं तो निश्चित ही यह फैसला अन्य राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए एक बड़ा सबक होगा। क्योंकि जो नेता मां-बेटियों और बहनों की इज्जत नहीं करता उसे इस देश और प्रदेश में सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है।

कुत्ते की पूछ की तरह है विजय शाह की चाल

देखा जाये तो विजय शाह के विवादित बयान उस कुत्ते की पूछ की तरह है जिसे 12 साल पोंगली में रखे तो भी वह निकलने के बाद तिरछी ही निकलेगी। ऐसा ही है विजय शाह का चरित्र। इससे पहले शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह चौहान को लेकर विवादित बयान दिया था जिसके बाद चौहान ने तत्काल प्रभाव से शाह से इस्तीफा लेकर उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। उसके बाद शाह ने स्कूल शिक्षा मंत्री रहते हुए एक समारोह में स्कूल की लड़कियों पर भद्दी टिप्पणी की थी जिसके बाद भी भाजपा और सत्ता, संगठन ने कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। यही कारण है कि शाह को दोनों ओर से बराबर ढील मिलती चली गई और वह इस तरह की अभद्रता भरी बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं।

शाह को मिले ऐसी सजा, जो बने मिसाल

एक महिला पत्रकार होने के नाते मैं यही चाहूंगी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और गृहमंत्री अमित शाह तीनों मिलकर विजय शाह की इस अभद्रता पर कार्रवाई वोट की राजनीति से उठकर करें तो निश्चित तौर पर वह एक मिसाल बनेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा निर्णय लेकर शाह को बर्खास्त कर दिया तो यह फैसला आने वाले कई वर्षों तक लोगों की स्मृति में बना रहेगा और दोबारा कोई गंवार नेता इस तरह की अभद्रता भरे बयान नहीं देगा।

कोर्ट का आदेश, शाह पर दर्ज करें एफआईआर

मंत्री विजय शाह पर एफआईआर की जाएगी। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है। डीजीपी को मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। 'ऑपरेशन सिंदूर' से सुर्खियों में आई कर्नल सोफिया को लेकर मंत्री ने टिप्पणी की थी। उन्हें आतंकियों का रिश्तेदार बता दिया था, जिसके बाद मंत्री के बयान के खिलाफ विरोध के स्वर उठे थे। आपत्तिजनक बयान पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। जबलपुर की खंडपीठ ने स्वप्रेरणा विजय शाह पर गंभीर आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज करने के निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री साय ने आत्म समर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से पीड़ितों को जारी की प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त

(पेज 1 से जारी)

उन्होंने कहा कि इसमें सरकार हर तरह की मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने नक्सली हिंसा के शिकार परिवारों से आत्मीयता से बातकर उनका हाल-चाल पूछा। उन्होंने घर-परिवार और उनके व्यवसाय की जानकारी ली। बातचीत के दौरान विभिन्न जिला मुख्यालयों से जुड़े हितग्राहियों ने पक्का आवास मिलने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद दिया।

वंचित परिवारों के लिए भी आवास की व्यवस्था

मुख्यमंत्री साय ने विभिन्न जिलों से मंत्रालय से वर्चुअली बड़ी संख्या में जुड़े हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य शासन ने केंद्र सरकार से विशेष आग्रह कर आत्म समर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता की शर्तों में नहीं आ पा रहे थे, उनके लिए 15 हजार आवास स्वीकृत कराया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने संवेदनशीलता और गंभीरता से हमारे निवेदन को मंजूरी दी और वंचित परिवारों के लिए भी आवास की व्यवस्था की।

40-40 हजार रुपए की पहली किस्त जारी

यह अवसर ऐतिहासिक है। 2500 ऐसे परिवारों को जो नक्सलवाद छोड़कर मुख्य धारा में लौट आए हैं या नक्सल हिंसा से पीड़ित हैं, उनके पक्के आवासों के निर्माण के लिए 40-40 हजार रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। ये ऐसे परिवार हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता में नहीं आ पा रहे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में विभाग ने विशेष प्रयास कर भारत सरकार से ये आवास मंजूर कराए हैं। साय ने कहा कि राज्य में नक्सलवाद को समाप्त करने का अभियान अब अंतिम चरण में है। बस्तर के लोगों के मन से अब आतंक का डर हट जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे मुख्य धारा में आएं। बस्तर की शांति और विकास के लिए यह जरूरी है। उन्होंने विशेष परियोजना के तहत हितग्राहियों के चिन्हांकन और इसे अमलीजामा पहनाने के लिए विभागीय अधिकारियों की पीठ थपथपाई और उन्हें धन्यवाद दिया।

विभागीय अधिकारी भी राशि अंतरण

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने कार्यक्रम में राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण के लक्ष्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। योजना के अगले चरण के लिए हितग्राहियों के सर्वेक्षण का काम भी तेजी से चल रहा है। सुकमा के सर्वाधिक 809 आत्म समर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों को मिली आवास की पहली किस्त, बीजापुर के 594 और नारायणपुर के 316 परिवार शामिल प्रधानमंत्री आवास योजना में विशेष परियोजना के तहत जिन 2500 आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के खातों में आवास निर्माण के लिए राशि अंतरित की गई, उनमें सर्वाधिक 809 परिवार सुकमा जिले के हैं। बीजापुर जिले के ऐसे 594, नारायणपुर के 316, बस्तर के 202, दंतेवाड़ा के 180, कोंडागांव के 166 और कांकेर के 138 परिवारों को आवास निर्माण के लिए राशि जारी की गई है।

कमलनाथ मुख्यमंत्री होते तो आज किसानों का कर्जा माफ हो जाता

(पेज 1 से जारी)

2018 में कांग्रेस सरकार बनते ही किसानों की कर्ज माफी शुरू कर दी गई और 27 लाख किसानों का कर्ज माफ भी कर दिया था। कमलनाथ यदि अपने शासन के पांच साल पूरे करते तो आज प्रदेश के सभी किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्जा माफ हो जाता लेकिन किसानों का यह दुर्भाग्य ही था कि उनका शासन पूरा न हो सका। आज किसानों को भी लग रहा होगा कि यदि कमलनाथ होते तो हमें कर्ज से राहत मिल जाती।

किसानों की अनदेखी कर रही बीजेपी सरकार

प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरते ही प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ की कर्जमाफी वाली योजना को बंद कर दिया। किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। फिर 2023 में डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। इन दोनों के कार्यकाल में आज तक किसानों की अनदेखी की जा रही है। कर्जमाफी के अलावा भी किसानों को कई परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। यूरिया की किल्लत, उत्पादों का सही दाम न मिलना, कीटनाशक के दामों में बढ़ोत्तरी जैसे बुनियादी मुद्दों हैं जिन पर सरकार का ध्यान ही नहीं दे रही है।

उपलब्धियों से भरा रहा कमलनाथ का शासन

कमलनाथ सरकार ने अपने शासन में विकास के नए कीर्तिमान गढ़े और कमजोर वर्गों को नई ताकत दी। कमलनाथ के नेतृत्व में ऐतिहासिक फैसले लिए। जिनकी वजह से प्रदेश को एक नई गति मिली।

जय किसान ऋण माफी योजना: प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ होगा, यह ऐलान 2018 विधानसभा चुनाव के 06 महीने पहले कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मंदसौर गोलीकांड की बरसी पर कर चुके थे। वहीं उन्होंने चुनावी सभाओं में 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया। कमलनाथ ने 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले किसान कर्ज माफी के आदेश पर दस्तखत किए। हालांकि कमलनाथ सरकार ने पहले 50 हजार तक के 20 लाख 10 हजार 690 किसानों का कर्जा माफ किया। कमलनाथ सरकार ने घोषणा की थी कि किसानों का 02 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा लेकिन खजाने की हालत कमजोर होने के कारण कमलनाथ को कर्ज माफी की प्रक्रिया चरणबद्ध चलानी पड़ी। कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी के दूसरे चरण की शुरुआत की थी जिसमें 50 हजार से लेकर एक लाख तक का किसानों का कर्जा माफ किया जा रहा था, जिनकी संख्या करीब 12 लाख थी।

पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण: प्रदेश की आधी से अधिक आबादी पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया गया। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी गई।

हाईटेक गौशाला निर्माण: चुनाव के वक्त कमलनाथ ने उन योजनाओं पर ज्यादा फोकस किया था, जिनको लेकर बीजेपी सियासत करती रहती है। कमलनाथ ने वचन दिया था कि वह प्रदेश में एक हजार आधुनिक गौशालाओं का निर्माण करेंगे। इस कड़ी में उन्होंने प्रदेश में 300 स्मार्ट गौशाला बनाने की शुरुआत की।

ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक फैसले: बिजली उपभोक्ताओं को भी मंत्रिमंडल ने एक नई सौगात दी। कुल 100 यूनिट तक की खपत पर 100 रुपये तक बिजली बिल देने, 150 यूनिट बिजली जलने पर 50 यूनिट पर निर्धारित बिजली दर लेने और 100 यूनिट पर 100 रुपये का फिक्स चार्ज लेने का फैसला लिया गया। इससे गरीबों के साथ ही मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली। साथ ही दस हॉर्स पावर तक के कृषि उपभोक्ताओं की विद्युत बिल राशि को आधा करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए इंदिरा किसान ज्योति योजना लागू की गई।

आदिवासियों को संरक्षण, सम्मान: आदिवासी वर्ग के हितों का संरक्षण करते हुए तेंदूपत्ता संग्रहण दर प्रति मानक बोरा दो हजार से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का निर्णय लिया गया। तेंदूपत्ता मजदूरी और बोनस राशि का भुगतान नकद करने का भी निर्णय हुआ। आदिवासी संस्कृति के देव स्थानों के संरक्षण के लिए उनका जीर्णोद्धार शासन द्वारा करने का निर्णय हुआ। आदिवासी भाइयों को ऋण से पूरी तरह मुक्ति दिलाने के लिए साहूकारी ऋण को माफ करने का फैसला हुआ।

निवेश को प्रोत्साहन: उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लैंड पूलिंग योजना 2019 को प्रायोगिक तौर पर लागू करने की नीति स्वीकृत हुई। अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए डाटा सेंटर स्थापना के लिए भूमि मूल्य पर 75 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय भी लिया गया। उद्यमियों और स्टार्ट अप को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसएमई विकास नीति का अनुमोदन किया गया।

पर्यटन के क्षेत्र में लिए अहम फैसले: पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने के लिए नयी ब्रांडेड होटल प्रोत्साहन नीति एवं पर्यटन नीति 2016 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई। रिसॉर्ट वार लाइसेंस को सरल बनाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर निर्मित करने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना अनुमोदित की गई।

कन्यादान योजना: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत शिवराज सिंह के कार्यकाल में विवाह योग्य कन्या के लिए शादी के समय सरकार द्वारा 28 हजार दिए जाते थे। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही इस राशि को 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार कर दिया।

सातवें वेतन आयोग को मंजूरी: कमलनाथ सरकार ने अध्यापक और संविदा शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की मंजूरी दी। साथ में स्कूलों से लंबित पड़ी तबादला नीति भी बनाई। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। कई विभागों में संविदा कर्मचारी नियमित कर दिए गए।

सरकार पारदर्शिता और जनभागीदारी की भावना से कार्य कर रही हैः मुख्यमंत्री साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह सरकार पारदर्शिता और जनभागीदारी की भावना से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार बनने के बाद 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 15 हजार विशेष मकानों की स्वीकृति दी गई है। महतारी वंदन योजना का लाभ सभी पात्र बहनों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की है। जमीन की रजिस्ट्री के साथ अब नामांतरण की प्रक्रिया भी स्वतः पूर्ण होगी। हक त्याग अब केवल 500 रुपये में हो रहा है। प्रदेश के 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिन्हें आगामी एक वर्ष में सभी ग्राम पंचायतों तक विस्तारित किया जाएगा।

132 केवी सब स्टेशन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन्नयन, हायर सेकेंडरी स्कूल उन्नयन की घोषणाएं

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम सीतागांव में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह भी उपस्थित थे।

सुशासन तिहार के तृतीय चरण अंतर्गत आज के समाधान शिविर में क्षेत्र की 8 ग्राम पंचायतों—सीतागांव, मदनवाड़ा, कारेकट्टा, हलांजुर, हुरेली, कंटाडी, कोहका, हलोरा—को क्लस्टर के रूप में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री साय ने इन पंचायतों के हितग्राहियों से सीधा संवाद कर शासन की योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की जानकारी ली और उनकी समस्याएं सुनीं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार 2025 मनाया जा रहा है। हमारी सरकार को कार्यभार संभाले डेढ़ वर्ष हुआ है और इस दौरान हम निरंतर जनता के बीच पहुंचकर योजनाओं के प्रभाव और लाभ का आंकलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि नया रायपुर में स्थापित आदिवासी संग्रहालय जनजातीय संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राज्य सरकार नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है और मार्च 2026 तक इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सीतागांव उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नयन करने, मोहला में बस स्टैंड और छात्रावास का निर्माण करने, सीतापुर में हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन करने और अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में 132 केवी सब स्टेशन की स्थापना की घोषणा की। इस अवसर पर विभिन्न जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

सबसे विवादित जनपद सीईओ चेतना पाटिल का एक और कारनामा उजागर

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। हमेशा विवादों में घिरी रहने वाली जनपद सीईओ चेतना पाटिल ने मुख्यमंत्री कन्या दान योजना कुछ जोड़ों को वंचित रखा हैं। टिमरनी विकासखंड की जनपद सीईओ चेतना पाटील शासन की योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वन नहीं कर पा रही है। इसका नजारा जनपद पंचायत टिमरनी में देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में एक जोड़ा शादी से वंचित रह गया। जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत टेमरू बहार में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह होना था। विभागीय रूप से सम्मेलन को कैंसिल कर दिया गया और इसकी जानकारी क्षेत्र के लोगों को नहीं लग पाई जिसके कारण नवयुवक जोड़ा शादी से वंचित रह गया। विकासखंड की जनपद पंचायत टिमरनी में दूल्हा दुल्हन के बेस में एवं परिवार के साथ महिला चुनुर्ग जनपद पंचायत टिमरनी पहुंचे दूल्हा कॉपल बीजोने एवं दुल्हन रिया महाजन जो कि इंदौर से है। जोड़ा नंबर 57 जनपद पंचायत टिमरनी पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया है कि हमने पूर्व में फॉर्म भी भर दिए थे और टेमरूबहार में शादी होना था। हमें जानकारी लगी है कि वह कैंसिल हो गया है। हम इतने दूर से हजारों रुपए खर्च कर शादी के लिए आए थे। परिवार वालों के साथ तो जानकारी लगी कि सम्मेलन कैंसिल हो गया है। हमने पूर्व में पंफलेट में छपे नंबरों पर भी दो-तीन दिन पहले फोन लगाया लेकिन पंफलेट में जो तीन-चार नंबर दिए हुए थे, उनमें किसी ने फोन भी नहीं उठाया और ना ही जनपद वालों ने हमें फोन से संपर्क किया। लड़के पक्ष एवं लड़की पक्ष के घर वालों ने बताया कि जनपद पंचायत से हमें किसी प्रकार से जानकारी नहीं दी गई और ना ही हमें फोन लगाया गया। अब हम क्या करें, हमें तो आप कोर्ट में जाकर ही शादी करनी पड़ेगी।

जनपद पंचायत में नहीं लगाया सूचना पटल पर नोटिस बोर्ड

अगर सम्मेलन की दिनांक 14 तारीख की गई थी तो उसकी सूचना जनपद के सूचना पटल पर तो लगाए होते इस संबंध में प्रेस नेट भी जारी किए जाते हैं परंतु जनपद सीईओ चेतना पाटिल खुद ही जजमेंट कर लेती हैं। अब देखना यह होगा कि नवयुवक जोड़े को न्याय मिलेगा या सब यू ही छोड़ दिया जाएगा।

डॉ. विक्रम राव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

-अमित राय

जगत प्रवाह. लखनऊ। वरिष्ठ पत्रकार और इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय के. विक्रम राव का भैंसाकुंड श्मशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अन्तिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सहित बड़ी संख्या में राजनेता, अधिकारी और पत्रकार मौजूद थे। डॉ. राव के पार्थिव शरीर को बड़े बेटे सुदेव राव ने मुखाग्नि दी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टुकड़ी ने गार्ड ऑफ आनर दिया। इससे पूर्व पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए यू.पी. प्रेस क्लब में रखा गया, जहां उनकी पत्नी डॉ. सुधा राव, बेटी विनीता राव और छोटे बेटे विश्वदेव राव तथा बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। यू.पी. वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी, लखनऊ मण्डल अध्यक्ष शिव शरण सिंह और यू.पी. प्रेस क्लब के अध्यक्ष रवीन्द्र कुमार सिंह ने पत्रकार संगठनों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा शोक व्यक्त करने वालों में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना, नंद गोपाल नंदी, नितिन अग्रवाल, ट्रेड यूनियन नेता उमाशंकर मिश्रा, विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान, पूर्व मंत्री राजेन्द्र चौधरी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ के संयोजक राजपाल कश्यप, उत्तर प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित, उत्तर प्रदेश क्षत्रिय समन्वय समिति के संयोजक प्रदीप सिंह बब्बू, अपना दल के प्रवक्ता संजीव सिंह राठौड़, एन.सी.पी. नेता सिराज मेंहदी, इंसराम अली, पत्रकार पुण्य प्रसून बाजपेई, हेमंत शर्मा, अमिताभ अग्निहोत्री, अवधेश कुमार, विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, आरएलडी नेता अनिल दुबे, विधान परिषद सदस्य महेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, भाजपा प्रवक्ता एसएन सिंह, संपादक टाइम्स आफ इंडिया प्रवीण कुमार, संपादक हिंदुस्तान टाइम्स प्रियांशु मिश्रा आदि शामिल थे।

आबकारी विभाग द्वारा 22,000 कीमत की अवैध शराब जप्त

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। कलेक्टर सोनिया मीना के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में चुत नर्मदापुरम 'अ' आबकारी टीम द्वारा नर्मदापुरम शहर के बालागंज सिकलीकर मोहल्ला कोठी बाजार सब्जी मंडी सहित अनेक संदिग्ध स्थलों पर दबिश एवं तलाशी की कार्यवाही की। तलाशी में 3 पेटी देशी शराब, 1 पेटी (48 पांव) व्हिस्की एवं 1 पेटी केन बीयर जप्त की गई। आरोपियों पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34.1 (क) के तहत 04 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। जप्त की गई सामग्री की अनुमानित कीमत 22000 है। कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी राहुल ढोके आबकारी उपनिरीक्षक सुयश फौजदार, वसुदेवाचार्य त्रिपाठी, राजेश साहू, कृष्ण कुमार पड़रिया, आबकारी आरक्षक गणपति बोबडे, विकाश लोखंडे, गोपाल रघुवंशी, दुर्गेश पटारिया, नगरसैनिक मोहन यादव का सराहनीय योगदान रहा। आबकारी दल द्वारा सूचना संकलित कर इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

सम्पादकीय

छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री साय की अग्रणी पहल

'नक्सलमुक्त भारत' बनाने की दिशा में नक्सली आतंक के विरुद्ध छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा के कुर्रेगुट्टालु पहाड़ पर चलाए गए अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया है। ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, महानिदेशक, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF); पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ अरुण देव गौतम और एडीजी छत्तीसगढ़ ने रायपुर में एक संयुक्त प्रेस वार्ता में अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। छत्तीसगढ़ पुलिस और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों का अभेद्य गढ़ समझे जाने वाले कुर्रेगुट्टालु पहाड़ पर 21 दिन तक चली मुठभेड़ में 16 वर्दीधारी महिला नक्सलियों सहित कुल 31 नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए हैं। अब तक 28 नक्सलियों की शिनाख्त हो चुकी है, जिन पर कुल 1 करोड़ 72 लाख रूपये का इनाम घोषित था। 21 अप्रैल से 11 मई 2025 तक चले नक्सल विरोधी अभियान में मुठभेड़ स्थल से बरामद शव प्रतिबंधित, अवैध और नक्सलियों के सबसे मजबूत सशस्त्र संगठन PLGA बटालियन, सीआरसी कंपनी एवं तेलंगाना स्टेट कमेटी के कैडर के हो सकते हैं। सुकमा एवं बीजापुर का सीमावर्ती क्षेत्र नक्सलियों के सबसे मजबूत सशस्त्र संगठन PLGA बटालियन, सीआरसी कंपनी एवं तेलंगाना स्टेट कमेटी सहित अनेक शीर्ष काडर्स की शरणस्थली था। इस क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने नए सुरक्षा कैम्पों की स्थापना की, जिसके कारण नक्सलियों ने यूनिफाइड कमांड का गठन कर वहां से बीजापुर, छत्तीसगढ़ एवं मुलुगु, तेलंगाना की सीमा पर अभेद्य समझे जाने वाले कुर्रेगुट्टालु पहाड़ पर शरण ली। KGH लगभग 60 किमी लम्बा एवं 5 किमी से लेकर 20 किमी चौड़ा अत्यन्त दुष्कर पहाड़ी क्षेत्र है, जिसकी भौगोलिक परिस्थिति बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण है। नक्सलियों ने पिछले ढाई वर्ष में क्षेत्र में अपना बेस तैयार किया, जो उनके लगभग 300-350 आर्म्ड काडर्स सहित PLGA बटालियन के टेक्निकल डिपार्टमेन्ट (टीडी यूनिट) एवं अन्य महत्वपूर्ण संगठनों की शरणस्थली थी। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पूर्ण एवं पुख्ता योजना तैयार कर सुरक्षा बलों ने 21 अप्रैल, 2025 से एक संयुक्त ऑपरेशन शुरु किया। अभियान में अब तक कुल 214 नक्सली ठिकाने और बंकर नष्ट किए जा चुके हैं और तलाशी के दौरान कुल 450 आईईडी, 818 बीजीएल शेल, 899 बंडल कॉर्डेक्स, डेटोनेटर और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की जा चुकी है। इसके अलावा लगभग 12 हजार किलोग्राम खाने-पीने का सामान भी बरामद किया गया है। 21 दिनों तक लगातार चले नक्सल विरोधी अभियान के दौरान संभावना है कि अभियान के दौरान कई वरिष्ठ नक्सली काडर या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अभियान के अंतर्गत सुरक्षाबलों ने नक्सलियों की चार तकनीकी इकाईयों को भी नष्ट किया, जिनका उपयोग बीजीएल शेल, देसी हथियार, IED और अन्य घातक हथियारों के निर्माण के लिए किया जा रहा था। अभियान के दौरान विभिन्न आईईडी विस्फोटों में कोबरा, एसटीएफ और डीआरजी के कुल 18 जवान घायल हुए। सभी घायल जवान अब खतरे से बाहर हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में सर्वोत्तम उपचार प्रदान किया जा रहा है। कुर्रेगुट्टालु पहाड़ी की परिस्थितियां बेहद कठिन हैं और वहां दिन का तापमान 45 डिग्री से अधिक होने के कारण अनेक जवान डिहाईड्रेशन के शिकार हुए। इसके बावजूद भी जवानों के मनोबल में कोई कमी नहीं आई और उन्होंने पूरे साहस और जोश के साथ नक्सलियों के विरुद्ध अभियान जारी रखा।

वर्ष 2024 में नक्सल विरोधी अभियान में प्राप्त सफलता को आगे बढ़ाते हुए सुरक्षा बलों ने वर्ष 2025 के 04 महीने में 197 हार्डकोर नक्सलियों को न्यूट्रलाइज्ड किया है। वर्ष 2014 में जहां 35 जिले नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित थे, 2025 में संख्या घटकर मात्र 6 रह गई है। इसी प्रकार नक्सलवाद प्रभावित जिले 126 से घटकर मात्र 18 रह गए हैं। 2014 में 76 जिलों के 330 थानों में 1080 नक्सली घटनाएं दर्ज की गई, जबकि 2024 में 42 जिलों के सिर्फ 151 थानों में 374 घटनाएं ही दर्ज हुई हैं। 2014 में 88 सुरक्षाकर्मी नक्सली हिंसा में बलिदान हुए थे, जो 2024 में घटकर 19 रह गई है। मुठभेड़ों में मारे गए नक्सलियों की संख्या 63 से बढ़कर 2089 तक पहुंच गई है। वर्ष 2024 में 928 और 2025 के पहले 4 महीनों में अब तक 718 सरेंडर हो चुके हैं। केन्द्रीय बलों ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर 2019 से 2025 के दौरान विभिन्न प्रकार के कुल 320 कैंप नक्सल प्रभावित राज्यों में स्थापित किए हैं। इन कैंपों में 68 नाइट लैंडिंग हैलीपैड भी बनाए गए हैं।

सियासी गहमागहमी

क्या विजय शाह की धमकी से भय में आ गई भाजपा?

मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने पिछले दिनों सेना की ऑफिसर और देश की बेटी कर्नल सौफिया कुरैशी पर जिस तरह की अभद्र टिप्पणी की थी उसके बाद पूरे देश में शाह के खिलाफ गुस्से का गुबार उबल रहा है। हालत यह है कि हर तरफ शाह के इस्तीफे की मांग उठ रही है। लेकिन रोचक बात यह है कि न तो मोहन सरकार के किसी व्यक्ति ने और न ही भाजपा तथा संगठन ने शाह से इस्तीफे की पेशकश की। हर कोई बस शाह के ऊपर कोर्ट द्वारा की जा रही कानूनी कार्यवाही की दुहाई दे रहा है। इसी बीच सुनने में आया कि मोहन सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री पिछले दिनों शाह के पास इस्तीफा देने की बात कहने के लिए गये। लेकिन शाह ने मंत्री को भी दो टूक सुनाते हुए कह दिया कि अगर मुझ पर इस्तीफे का दबाव बनाया तो मैं आदिवासी संगठन बनाकर भाजपा को पटरी से नीचे उतार दूंगा। अब शाह की यह दादागिरी को भाजपा और संगठन कैसे पचा पाता है यह आने वाला समय बतायेगा।

'ऑपरेशन सिंदूर' को सराहा

पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भारतीय सेना द्वारा चलाये गये 'ऑपरेशन सिंदूर' पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान-आधिकारिक कश्मीर में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने लिखा रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान और पीओके में उन आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जहां से भारत में आतंकवादी हमलों की साजिश रची जाती थी और उन्हें संचालित किया जाता था। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस कार्रवाई में कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह हमले पूरी तरह से लक्षित, सटीक और बिना बढ़े हुए थे, ताकि पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं को नुकसान न पहुंचे।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

गुजरात समाचार को खामोश करने की कोशिश सिर्फ एक अखबार की नहीं, पूरे लोकतंत्र की आवाज दबाने की एक और साजिश है।
जब सत्ता को आईना दिखाने वाले अखबारों पर ताले लगाए जाते है, तब समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है।
बाहुबली शाह की गिरफ्तारी डर की उसी राजनीति का हिस्सा है, जो अब मोदी सरकार की पहचान बन चुकी है।
देश न डंडे से चलेगा, न डर से - भारत चलेगा सच और संविधान से।-

राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के मंत्री लगातार भारतीय सेना का अपमान कर रहे है। पहले एक मंत्री ने भारतीय सेना की कर्नल को आतंकवादियों की बहन कहकर अपमानित किया और अब उपमुख्यमंत्री पूरी सेना को लेकर आपत्तिजनक बयान दे रहे है।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

सलमान खुर्शीद लेखक और कानून शिक्षक के रूप में भी विख्यात हैं

समता पाठक/जगत प्रवाह

सलमान खुर्शीद एक भारतीय राजनेता हैं। 01 जनवरी 1953 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में जन्मे। वे भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री खुर्शीद आलम खान के पुत्र और भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के नाना हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जाने-माने राजनेता हैं। उन्होंने सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, पटना और दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड से पढ़ाई की। उन्होंने सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली से बी.ए. (अंग्रेजी और न्यायशास्त्र) की डिग्री हासिल की और बाद में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सेंट एडमंड हॉल से एम.ए., बैचलर ऑफ सिविल लॉ किया। उनका राजनीतिक जीवन 1980 के दशक की शुरुआत में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष कर्तव्य पर एक अधिकारी के रूप में शुरू हुआ। बाद में वे भारत सरकार में वाणिज्य उप मंत्री बने। 1991 में, उन्होंने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संसद के लिए चुनाव जीता और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा उन्हें विदेश राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। सलमान खुर्शीद एक भारतीय राजनीतिज्ञ, नामित वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रख्यात लेखक और कानून शिक्षक हैं। वह विदेश मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं वह एक वकील और एक लेखक है जो 2009 की आम चुनाव में फर्रुखाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। इससे पहले वह फर्रुखाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं लोकसभा (1991-1996) के लिए चुने गए थे। वह जून 1991 में वाणिज्य के केंद्रीय उपमंत्री बने और बाद में विदेश मामलों के राज्यमंत्री (जनवरी 1993-जून 1996) बन गए। उन्होंने 1981 में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में एक विशेष अधिकारी के रूप में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के तहत अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। खुर्शीद दिल्ली और ऑक्सफोर्ड में अपने छात्र जीवन से ही नाटकों में लेखन और अभिनय में गहराई से शामिल रहे हैं। वह रूपा एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित नाटक सन्स ऑफ बाबर के लेखक हैं, जिसका मंचन टॉम ऑल्टर के साथ दिल्ली के लाल किले में किया गया है। सलमान खुर्शीद 1990 में प्रकाशित "द कंटेम्परी कंजर्वेटिव: सिलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ धीरेन भगत के संपादक भी रह चुके हैं। अक्टूबर 2021 में, खुर्शीद ने अयोध्या विवाद के आसपास धर्मनिरपेक्षता में भारत की गिरावट के बारे में लिखते हुए, सनराइज ओवर अयोध्या: नेशनहुड इन अवर टाइम्स प्रकाशित किया। भाजपा नेताओं ने किताब का एक अंश साझा किया और खुर्शीद के हिंदुत्व और कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के बीच समानता लाने के प्रयास के बारे में विवाद खड़ा कर दिया। विवाद के परिणामस्वरूप उनके नैनीताल के घर में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर एक मुकदमा, सनराइज ओवर अयोध्या: नेशनहुड इन अवर टाइम्स पुस्तक के प्रकाशन, प्रसार और बिक्री को रोकना चाहता है। दिल्ली की अदालत ने 18 नवंबर 2021 को मुकदमे में एकपक्षीय निषेधाज्ञा देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, "इस अदालत की राय में, न तो प्रथम दृष्टया मामला है और न ही वादी के पक्ष में अंतरिम पूर्व-पक्षीय निषेधाज्ञा देने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति मौजूद है। न्यायाधीश ने कहा, "इसके अलावा, वादी यह स्थापित करने में विफल रहा है कि सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है। इसलिए, इस स्तर पर अंतरिम एकतरफा राहत के लिए प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि लेखक और प्रकाशक को किताब लिखने और प्रकाशित करने का अधिकार है।

सीखने से भी ज़्यादा ज़रूरी है "भूलना"

खुशहाल जीवन का मूल मंत्र: "जो बीत गई, सो बात गई"

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

हम हर समय कुछ नया सीखना चाहते हैं लेकिन "क्या आप जानते हैं, सीखने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, भूलना! हाँ, आपने सही सुना। हमारा दिमाग सुपर कम्प्यूटर की तरह है, इसमें गैर जरूरी पुराना डाटा रखेंगे तो यह हैंग होने लगेगा। सरल शब्दों में कहूं तो अपने जीवन को खाली स्लेट समझिये। अगर आप उस पर से पुरानी लिखावट नहीं मिटाएंगे, तो नया कैसे लिख पाएंगे? "भूलना" सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आजादी है, अपने मन को हल्का करने की, नई उम्मीदों के लिए जगह बनाने की।

हम हर दिन नई चीजें सीखने का प्रयास करते हैं, नई आदतें अपनाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम पुरानी सोच के पैटर्न, नकारात्मक भावनाओं और व्यर्थ के डर को छोड़ने में हिचकिचाते हैं। हमें यह जानना होगा कि किन बातों को अपने मस्तिष्क से निकाल देना है, किन अनुभवों से सबक लेकर उन्हें पीछे छोड़ देना है, और किन नकारात्मक भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देना है।

जब हम अपने मन को पुरानी और अनावश्यक बातों से मुक्त करते हैं, तो हमारे पास नई चीजों को सीखने, नए विचारों को अपनाने और नए अवसरों को पहचानने के लिए अधिक जगह और ऊर्जा बचती है। बीती सारी बिसार दे, आगे की सुध ले– यह केवल एक सलाह नहीं, बल्कि एक सफल और खुशहाल जीवन का मूल मंत्र है।

आजकल हर कोई बॉडी को डिटॉक्स करने की बात कर रहा है, लेकिन क्या आपने कभी अपने मन को डिटॉक्स करने के बारे में सोचा है? आपका मन ही तो है जो आपकी दुनिया बनाता है। तो क्यों न उसे साफ किया जाए, नकारात्मक विचारों के कचरे को बाहर निकाला जाए? मैं आपको बताता हूँ 6 सुपर पावरफुल तरीके जिनसे आप अपने मन को डिटॉक्स कर सकते हैं और एक शांत, सकारात्मक जीवन की ओर बढ़ सकते हैं

मन का डिटॉक्स: अचूक तरीके नकारात्मकता को अलविदा कहने के!

अतीत को विदाई: "आज एक नया दिन है"

किसी भी पुरानी बात को पकड़कर मत बैठे रहिए। अतीत एक गुजरा हुआ कल है, उसे जाने दीजिए। नए पत्ते तभी आते हैं जब पुराने गिर जाते हैं। हर सुबह खुद से कहिए, "आज एक नया दिन है, मैं पिछली तकलीफों और गलतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ूँगा।" एक कागज पर उस बात, डर या गुस्से को लिखिए जिसे आप छोड़ना चाहते हैं और फिर उसे जला दीजिए। याद रखिए, अतीत की गठरी आपके कंधों पर बोझ बनकर आपके भविष्य के रास्ते में रुकावट डालेगी। जब तक आप पुराना छोड़ेंगे नहीं, नया कैसे अपनाएंगे?

यह है असली "मेंटल डिटॉक्स"

रोज रात को सोने से पहले 05 मिनट निकालिए और लिखिए कि आज आपने क्या नया सीखा, कौन सी बात आपको बेकार लगी और आप क्या छोड़ सकते हैं। उस लिखे हुए पन्ने को फाड़ दीजिए या जला दीजिए, यही है असली "मेंटल डिटॉक्स"। लिखने से आपके विचार स्पष्ट होते हैं और जब आप किसी चीज को "छोड़ने" का फैसला लिख देते हैं तो आपका मन उसे स्वीकार करने लगता है। यह नकारात्मकता को बाहर निकालने का एक शक्तिशाली तरीका है।

मन की सफाई: मैं गलतफहमी को अलविदा कह सकता हूँ!

जैसे आप अपनी अलमारी से पुराने कपड़े निकालते हैं, वैसे ही अपने दिमाग से पुरानी, नकारात्मक सोच को बाहर निकालिए। दिमाग की अलमारी में जमे नकारात्मक विचारों के कचरे को साफ करना जरूरी है, तभी आप नई सकारात्मक विचारों की किताबें रख पाएंगे। हर रविवार को "माइंड क्लीनिंग डे" मनाइए। खुद से पूछिए, "इस हफ्ते मैं कौन सी नकारात्मक आदत, डर या गलतफहमी को अलविदा कह सकता हूँ?" उसे मानसिक रूप से कचरे की तरह बाहर फेंक दीजिए।

घर की सफाई की तरह मन की सफाई भी जरूरी है, वरना पुरानी सोच धीरे-धीरे जहर बन जाती है।

सकारात्मक संगत: नए लोग, नए विचार!

उन लोगों से दूरी बनाइए जो आपको पीछे खींचते हैं। यह सच है कि "आप जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, वैसे ही बन जाते हैं।" अपने जीवन के दायरे से उन लोगों को कम कीजिए जो हमेशा शिकायत करते हैं, पुरानी बातों को दोहराते हैं और नए विचारों को नकारते हैं। इसके बजाय, उन लोगों के साथ जुड़िए जो आपको प्रेरित करते हैं, जो सकारात्मक और उत्साही हैं। आपका आसपास का माहौल आपकी सोच को आकार देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सोच ताजा रहे, तो अपने आसपास ताजा विचारों वाले लोगों को रखिए।

अहंकार का त्याग: सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें!

यह मान लीजिए कि आपको सब कुछ नहीं आता। "जो बर्तन भरा हुआ है, उसमें और कुछ नहीं डाला जा सकता।" हर दिन एक नई चीज सीखने का लक्ष्य रखिए, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। जब कोई नई बात सुनें, तो पहले ध्यान से सुनें, फिर उस पर विचार करें और अंत में अपनी राय दें। "मुझे पता है" कहने की बजाय "मैं सीखना चाहता हूँ" कहिए। अहंकार ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। जो झुकता है, वही आगे बढ़ता है।

मौन की शक्ति: भीतर की आवाज़ को सुनें!

मौन में वह शक्ति है जो दुनिया के शोर को शांत कर देती है। "जब आप चुप होते हैं, तो आपकी आत्मा बोलती है।" हर दिन 5-10 मिनट के लिए मौन का अभ्यास कीजिए। इस दौरान सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जब मन में विचार आएं, तो उन्हें बादलों की तरह आते-जाते देखिए, बिना किसी जुड़ाव के। मौन आपके मन का दर्पण है। जब आप शांत होते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। यह आपके मन को अंदर से डिटॉक्स करने का एक अद्भुत तरीका है।

अब आजाद है बलूचिस्तान

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी लड़ाई में ऐसे साफ संकेत मिलने लगे थे कि पाकिस्तान का भूगोल बदलने जा रहा है। अब बलूच नेता मीर यार बलूच ने ऐलान किया है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से पृथक एक अलग स्वतंत्र देश है। उन्होंने भारत और वैश्विक समुदाय से बलूचिस्तान की आजादी हेतु समर्थन देने की मांग की है। मीर ने कहा है कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है, इसलिए दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। यह हमारा राष्ट्रीय निर्णय है कि हम अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेंगे। बलूच नेता ने भारतीय नागरिकों से आग्रह किया है कि सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग और बुद्धिजीवी बलूचों को 'पाकिस्तान के अपने लोग' कहने से परहेज करें। क्योंकि अब हम पाकिस्तानी नहीं बलूचचिस्तानी हैं। बलूचियों ने संयुक्त राष्ट्र से भी स्वतंत्र देश मान लेने का आग्रह किया है।

पाक का बड़ा भू-भाग बलूचिस्तान प्रांत में लंबे समय से स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ रहा था, वह सफलता के शिखर पर है। बलूचिस्तान को नए देश के रूप में मान्यता मिल जाती है तो 1971 के बाद पाकिस्तान की भूमि पर दूसरा बड़ा विभाजन दिखाई देगा। 1971 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना को सैनिक मदद देकर पाक के दो टुकड़े कर दिए थे। 93 हजार पाक सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष हथियार डाल दिए थे। सैनिकों का इतना बड़ा समर्पण इस घटना से न तो पहले कभी हुआ और न ही बाद में ? बलूचों ने तो अपने सीमा क्षेत्र से पाक सैनिकों को खदेड़ कर और सरकारी इमारतों से पाकिस्तानी झंडा उतारकर, बलूचिस्तान का झंडा फहरा दिया। अब बलूच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए दिल्ली में बलूचिस्तान का दूतावास खोलने की मांग कर रहे हैं। बलूचों ने संयुक्त राष्ट्र से शांति रक्षक बल भेजने की भी मांग की है। प्रसिद्ध लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता मीर यार बलूच को बलूच के लोगों के अधिकारों की वकालात के लिए जाने जाते हैं। बलूचों ने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान में शांति रक्षक बल भेजने और पाक सेना को बलूच सीमा क्षेत्र से बाहर कर देने का आग्रह भी किया है। भारत ने तो ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाक और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद केवल आतंकी ठिकानों पर लक्ष्य साधकर उन्हें नष्ट किया। परंतु किसी सैन्य ढांचें को निशाना नहीं बनाया। किंतु मीरयार बलूच ने दावा किया है कि बलूच स्वतंत्रता सेनानियों ने डेरा बुगती में पाक के 100 गैस कुओं पर हमला किया। पाक सेना को बंकरों से खदेड़ दिया। अतएव अब पाक सेनाएं, अर्धसैनिक बल, पुलिस, आईएसआई और प्रशासन में कार्यरत सभी गैर बलूच अधिकारी तुरंत बलूचिस्तान छोड़ दें। यदि बलूच स्वतंत्र देष बन जाता है तो भारत-पाक युद्ध के बीच 1971 की तरह एक युगांतरकारी घटना देखने को मिलेगी, जिसमें बलूचों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव में भारत भी भागीदार हो सकता है। बलूचों की स्वतंत्रता की संभावना का अहसास पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने भी जताया है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान पर अब सेना और सरकार का नियंत्रण ढीला पड़ रहा है। यहां के हालात इतने खराब हैं कि सरकारी मंत्री तक बाहरी सुरक्षा के बिना बाहर नहीं निकल सकते हैं। सेना के जवान अपने ही देष में बंकरों में छिपे हैं।

बलूचिस्तान में विद्रोह की आग चरम पर है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आजादी की मांग करने वाला सबसे पुराना सशस्त्र अलगाववादी संगठन है। यह संगठन पहली बार 1970 में अस्तित्व में आया था। इसने जुल्फिकार अली भुट्टो के कार्यकाल में बलूचिस्तान प्रांत में सशस्त्र विद्रोह का शंखनाद कर किया था। कालांतर में सैनिक तानाशाह जियाउल हक द्वारा सत्ता हथियाने के बाद बलूच नेताओं के साथ बातचीत हुई, जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष विराम की स्थिति बन गई थी। नतीजतन बलूचिस्तान में सशस्त्र विद्रोह खत्म हो गया था और बीएलए का भी कोई वजूद नहीं रह गया था। किंतु कारगिल युद्ध के बाद सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्तापलट कर सत्ता हथिया ली। इसके बाद मुशर्रफ के संकेत पर साल 2000 में बलूचिस्तान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नवाबमिरी की हत्या कर दी गई और मुशर्रफ ने कुटिल चतुराई बरतते हुए पाक सेना से इस मामले में आरोपी के रूप में बलूच नेता खेरबख्श मिरी को गिरफ्तार करा दिया। इसके बाद फिनिक्स पक्षी की तरह बीएलए फिर उठ खड़ा हुआ। इसके बाद से ही जगह-जगह हमले शुरू हो गए। साल 2020 में एकाएक बीएलए की ताकत बढ़ गई और बलूचिस्तान के सरकारी प्रतिष्ठानों तथा सुरक्षाबलों पर हमलों की संख्या बढ़ती चली गई।

बीएलए बलूचिस्तान में चीन के प्रभाव को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करता है। उसका मानना है कि चीन बलूचिस्तान की प्राकृतिक संपदा को हड़पने का काम कर रहा है। इसी नजरिए से ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने के साथ एक बड़ा चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी बना रहा है। दरअसल भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के समय बलूचिस्तान को बलूचों की इच्छा के बिना बंदूक की जोर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। जबकि वे स्वयं को एक स्वतंत्र देष के रूप में देखना चाहते थे। अतएव पाक की स्वतंत्रता के समय से ही बलूचों का संघर्ष पाक सरकार और सेना से निरंतर बना हुआ है। बीएलए जब साल 2000 में वजूद में आया था तब इसके लड़ाकों की संख्या 6000 से भी ज्यादा थी। जिसमें करीब 150 आत्मघाती दस्ते शामिल थे। सरदार अकबर खान बुगती एक समय बलूचिस्तान के सर्वमान्य नेता रहे हैं। इसलिए वे बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। 26 अगस्त 2006 को पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने उनकी हत्या कर दी थी। तभी से यह संगठन पाक सेना से लोहा ले रहा है। वर्तमान में बलूच अलगाववादी और तालिबान के बीच निरंतर निकटता बढ़ रही है। वैसे भी अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के काबिज होने के बाद से पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। पाक सरकार ने भी स्वीकार किया है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ही बलूच लड़ाकों को प्रशिक्षित कर रहा है।

पाक की आजादी के साथ बलूचिस्तान का मुद्दा जुड़ा है। पाक की कुल भूमि का 43.6 फीसदी हिस्सा केवल बलूचिस्तान का है। लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है। करीब 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस हिस्से में सर्वाधिक बलूच है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,47,190 वर्ग किमी है। यहां हिंदू, सिख और ईसाई भी रहते हैं। इनमें आपस में खूब भाईचारा है। भगवान शिव की पत्नी सती का हिंगलाज मंदिर इसी बलूच क्षेत्र में आता है। अनेक मुसलमान भी देवी सती की पूजा-अर्चना करते हैं। क्योंकि ये धर्मांतरित है। यहां से कभी सांप्रदायिक दंगों की खबरें नहीं आती हैं। पाक और बलूचिस्तान के बीच संघर्ष 1945, 1958, 1962-63, 1973-77 में होता रहा है। 77 में पाक द्वारा दमन के बाद करीब 2 दशक तक शांति रही। लेकिन 1999 में परवेज मुशर्रफ सत्ता में आए तो उन्होंने बलूच भूमि पर सैनिक अड्डे खोल दिए। इसे बलूचों ने अपने क्षेत्र पर कब्जे की कोशिश माना और फिर से संघर्ष तेज हो गया। इसके बाद यहां कई अलगाववादी आंदोलन वजूद में आ गए। इनमें सबसे प्रमुख बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी प्रमुख है। पीओके और बलूचिस्तान पाक के लिए बहिष्कृत क्षेत्र हैं। पीओके की जमीन का इस्तेमाल वह, जहां भारत के खिलाफ शिविर लगाकर गरीब व लाचार मुस्लिम किशोरों को आतंकवादी बनाने का प्रशिक्षण देता रहा है, वहीं बलूचिस्तान की भूमि से खनिज व तेल का दोहन कर अपनी आर्थिक स्थिति बहाल किए हुए है।

बलूचिस्तान की कलात रियासत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा करने के बाद 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान में शामिल हो गया था। लेकिन बलूचिस्तान ने पाक में विलय को कभी स्वीकार नहीं किया। लिहाजा यहां अलगाव की आग निरंतर बनी रही है। नतीजतन 2001 में यहां 50 हजार लोगों की हत्या पाक सेना ने कर दी थी। इसके बाद 2006 में अत्याचार के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वाले 20 हजार सामाजिक कार्यकर्ताओं को अगवा कर लिया गया था, जिनका आज तक पता नहीं है। 2015 में 157 लोगों के अंग-भंग किए गए थे। फिलहाल पुलिस ने जाने-माने एक्टिविस्ट बाबा जान को भी हिरासत में लिया हुआ है। पिछले 20 साल से जारी दमन की इस सूची का खुलासा एक अमेरिकी संस्था ने किया है। वाशिंगटन में कार्यरत संस्था गिलगिट-बलूचिस्तान नेशनल कांग्रेस के सेंग सिरिंग ने मोदी द्वारा उठाए, इस सवाल का समर्थन किया है कि 'पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और बलूचिस्तान में लोगों पर होने वाले जुल्म एवं अत्याचार के बाबत पाक को दुनिया के समक्ष जवाब देना होगा ? पाक तो जवाब देने वाला नहीं है, लेकिन भारत की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह बलूचिस्तान की स्वतंत्रता में भागीदार बने?

बीमार झीलें पूरे समाज को बीमार कर सकती हैं

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

हमारे देश की झीलों ने सदियों से जीवनदायिनी भूमिका निभाई है। जल का भंडार होने के साथ ही ये पारिस्थितिकी, पर्यटन, कृषि और पेयजल स्रोत के रूप में हमारी अर्थव्यवस्था का भी आधार हैं। परंतु यदि ये "बीमार" हो जाएँ, तो उनका विषकाण सीधे हमारे स्वास्थ्य, समाज और आर्थिक तंत्र को जीवनदायिनी होने के बजाय रोगजनक बना देता है। "बीमार झीलें पूरे समाज को बीमार कर सकती हैं"। यह कथन केवल रूपक नहीं, बल्की सच का साक्षात् प्रतिबिंब है। इस चिंताजनक विषय पर सभी को विचार और समाधान ढूंढने की आवश्यकता है।

झीलों का पारिस्थितिक और सामाजिक महत्व है। झीलें अनेक जलजीवों जैसे मछलियों, जलीय मुद्रकों, कीटों तक को जीवन देती हैं। इससे वातावरण का संतुलन होता है। ताजे जलस्रोतों की उपस्थिति स्थानीय तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करती है। झीलें आजीविका का आधार भी है। मछुआरे, किसान और पर्यटक-उद्योग झीलों पर निर्भर हैं। तीर्थस्थल और समारोह इन झीलों के किनारे होते हैं, जो स्थानीय संस्कृति को पोषण देते हैं। लेकिन ये झीलें बीमार होती गईं। "बीमार झील" वह है, जिसके जल में जैव रासायनिक असंतुलन पैदा हो गया हो, जैविक तत्व अति-सीमित हो गए हों, जैसे कि अधिक पोषक तत्व (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस), भारी धातुएँ, रसायनिक प्रदूषक, प्लास्टिक कचरा और रोगजनक बैक्टीरिया तथा वायरस। ये सभी मिलकर झील के स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं। कृषि उर्वरकों और घरेलू सीवेज मिल जाने से जलीय शैवालों की अनियंत्रित वृद्धि, जिससे ऑक्सीजन की कमी और मछलियों की मृत्यु होती है। ठोस अपशिष्ट, कीटनाशक, जैविक अवशेष झील में मिलने से जल विषाक्त हो जाता है। दोहनशील वस्तुएँ जैसे माइक्रो प्लास्टिक और ठोस कचड़ा बिखरकर जलीय जीवों में समा जाती हैं, खाद्य श्रृंखला में विषाक्तता बढ़ाती है। जीवाणुजनित खतरा भी बना रहता है। उचित सफाई न होने पर हैजा, टाइफाइड, हैपेटाइटिस-ए जैसी संक्रामक बीमारियाँ फैला देती हैं।

भारत में कई प्रसिद्ध झीलें, जैसे उदयपुर की पिछोला झील, बैंगलोर की उल्केल झीलें और श्रीनगर का डल झील, "अस्पताल" की ओर बढ़ते दिखाई दे रही हैं। इनके संकट के कई कारण हैं। झीलों की सीमाओं में हो रहे मकान, होटलों व वॉटर फ्रंट डेवलपमेंट ने पानी के प्रवाह और पुनर्भरण को रोक दिया है। शहरी क्षेत्रों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कमी से गंदा पानी सीधे झीलों में जाता है। खेतों में छिड़के गए उर्वरक और कीटनाशक वर्षा-जल के साथ झीलों तक पहुँचकर तंत्रिका तंत्र और जनस्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। पर्यावरणीय नियमन जैसे बोर्ड, निगम, और स्थानीय निकाय अक्सर सतत निरीक्षण नहीं कर पाते, और नियम-उल्लंघन पर कार्रवाई कमजोर होती है।

दूषित जल पीने या स्नान करने से हेपेटाइटिस, पेट संबंधी संक्रमण, त्वचा रोग और नेफ्रोटिक्स जैसी बीमारियाँ फैलती हैं। मछुआरी समुदाय को मछलियों की मृत्यु से अन्नदाता व रोजगार खोना पड़ता है। पर्यटन उद्योग धंधे पर पड़ा संकट रोजगार के अवसर सिकुड़ जाते हैं। स्वस्थ झीलें भूमिगत जल को रिचार्ज करती हैं, बीमार झीलें यह कार्य नहीं कर पातीं, जिससे बोरवेल ड्रिलिंग बढ़ती है तथा भूजल स्तर घटता है। जलीय और तटीय परिसरों में जीवन की लहर मंद हो जाती है, पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। झीलों का अस्वास्थ्य केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक समस्या भी है। जब झीलें प्रदूषित होती हैं, तो उनका कचरा और दुर्गंध आसपास के बस्तियों में फैलता है। इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है, जिससे मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियाँ फैलती हैं। छात्रों की उपस्थिति घटती है, कार्यबल स्वास्थ्य-चंबलों से ग्रस्त होता है और बस्तियों का सामाजिक वातावरण बिगड़ता है। एक अस्वस्थ्य समाज का निर्माण होता है, जहाँ आर्थिक विकास की कल्पना धुंधली हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से सरकारी और निजी साझेदारी में कई झील पुनरुद्धार परियोजनाएँ चलाई गई हैं। तटीय पौधों की रखी गई बैंड सुरक्षित दिल्ली के ठोंगरवाड़ी झील इत्यादि में प्रयोग की गई। कई महानगरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं पर संचालन-व्यवस्थापन में लापरवाही से आउटपुट एवं गुणवत्ता घट रही है। स्वयंसेवी समूहों ने सफाई अभियान चलाए, पर वे महज नाटकीय आयोजन तक सिमित रह गए। इन प्रयासों से प्रारंभिक सुधार दिखने लगे हैं, पर वे सतत नहीं हुए। नियत फंडिंग का अभाव, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और स्थानीय सहभागिता का तंगी में रहना मुख्य बाधाएँ हैं।

झीलों को स्वस्थ एवं जीवन्त बनाने के लिए सामूहिक, तकनीकी और प्रबन्धकीय हल चाहिए। झील के परिसीमन को स्पष्ट मानचित्रों में अंकित करना चाहिए। पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर अतिक्रमण पर कड़ी निगरानी रखना चाहिए। प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना चाहिए और औद्योगिक और भागिक अपशिष्ट के लिए अलग प्लांट। ट्रीट किए पानी का सिंचाई, पार्किंग लोड स्केपिंग में पुनः उपयोग करें, जिससे झील में प्रवाह नियंत्रित हो। जैव-उपचार (Bioremediation) और इनोवेटिव तकनीक अपनाना चाहिए। लेकिन जैल, बायोकार्बन फिल्टर, वाटरलिलिस् या सौर बबलर से औद्योगिक रसायनों और जैविक प्रदूषण को हटाना आवश्यक है। स्थानीय पौधों जैसे रोपनि (पुंसरी), जलकुम्भी की नियंत्रित कटाई व उपयोग से पोषक तत्व संतुलन बनाए रखें। 'झील मित्र समूह' बनाएं, जिसमें आरक्षित स्थानीय निवासी, व्यापारी, स्कूल छात्र, और समाजसेवी शामिल हों।नियमित कार्यशालाओं, छापखानों, डॉक्यूमेंटों के माध्यम से झील स्वास्थ्य, सफाई और पोषक तत्वों के महत्व को समझाएँ। ड्रोन, स्मार्ट सेंसर, और GIS तकनीक से जलगुणवत्ता (pH, DO, BOD, COD) का सतत ट्रैक रखें।डेटा के आधार पर त्वरित अलर्ट सिस्टम और आकस्मिक कार्रवाई के लिए "ओपन डेटा पोर्टल" तैयार करें। 'हरित अधिभार' (Green Surcharge) के रूप में नगर निगम करों में मामूली बढ़ोतरी, जो केवल झील प्रबंधन में ही उपयोग हो। कॉर्पोरेट्स को टैक्स लाभ देकर झील पुनरोद्धार परियोजनाओं में निवेश की प्रेरणा दें। "बीमार झीलें पूरे समाज को बीमार कर सकती हैं"। यह वाक्य हमें जीवनदायिनी धरोहरों के प्रति हमारी लापरवाही की दहशत भरी सच्चाई से अवगत कराता है। यदि हमने आज इन्हें बचाने का संकल्प नहीं लिया, तो मानव-जीवन का जलचक्र ही सूख जाएगा। परंतु समाधान असंभव नहीं। कम उत्साहहीनता, तकनीकी नवाचार, कानूनी ईमानदारी और सामुदायिक सहभागिता से हम इन झीलों को फिर से स्वस्थ, स्वच्छ और संपन्न बना सकते हैं। यथार्थ समाधान का बीज तभी अंकुरित होगा, जब सरकार, विज्ञान, व्यवसाय, और समाज—सभी मिलकर 'स्वस्थ झील, स्वस्थ जीवन' के आदर्श पर चलें। यही हमारा अनिवार्य संदेश है, जो झीलें आज बीमार हैं, वे कल का जीवनदान बन सकती हैं। हमें बस मिलकर आज की कार्रवाई आरंभ करनी होगी, ताकि कल का पानी फिर से जीवनदायिनी बनकर बहे।

भूपेश बघेलः कई गंभीर अपराधों और घोटालों में संलिप्पता के बावजूद गिरफ्तारी नही, जॉच एजेंसियां पसोपेश में

(पेज 1 से जारी)

दिलचस्प बात यह है कि घोटालों में सबसे पहले बघेल के गिरोह में शामिल कई बड़े अफसरों और कारोबारियों का नाम सामने आया था। इनके ठिकानों पर छापेमारी के बाद कुछ चुनिंदा आरोपियों के चेहरे देखकर गिरफ्तारियां भी हुई थी और आरोपी जेल की हवा खा रहे हैं। इन्ही आरोपियों की तर्ज पर केन्द्रीय जांच एजेंसियों ने भूपेश बघेल के पुत्र चेतन्य बघेल फिर इसके बाद भूपेश बघेल के ठिकानों पर छापेमारी की थी। एजेंसियों ने प्रेस नोट जारी कर बघेल के कुकर्मों का ब्यौरा भी सार्वजनिक किया था। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ 2100 करोड़ के शराब घोटाले, 1500 करोड़ के महादेव एप घोटाले में नामदर्ज एफआईआर दर्ज हुई थी। घोटालों में भी बघेल की संलिप्पता के स्पष्ट प्रमाण एजेंसियों के हाथों में बताये जाते हैं। बावजूद इसके कानून के हाथ प्रदेश के दागी मुख्यमंत्री के गिरेबान तक नही पहुंच पाये हैं। कई बड़े आरोपी हवालात की सैर कर रहे हैं। यहां तक कि बघेल के लिये कमाऊ पुत्र साबित हुये तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा को भी जेल की चक्की पीसनी पड़ रही है। लेकिन भूपेश बघेल की गिरफ्तारी को लेकर एजेंसियों को सांप सूंघ गया है। ईडी और सीबीआई के सूत्र तस्दीक कर रहे हैं कि बघेल की गिरफ्तारी को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश केन्द्र और राज्य सरकार को प्राप्त नही हुये हैं। उनकी यह भी दलील है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपराधों का राजनीतिकरण कर कानूनी दांवपेचों से एजेंसियों की विवेचना को विवादित बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के कई बड़े आरोपियों की याचिकाएं कानूनी पटल पर सुर्खियां बटोर रही हैं। बघेल एण्ड कम्पनियों और उनकी गुर्गों को उनकी पूर्ण विवेचना और कानूनी प्रावधानों की कमजोर कार्यवाही के कारण अदालत कभी ईडी पर सवालियां निशान लगाते हुए ईपीआईआर खारिज कर रही है और जमानत भी दे रही है।

आम जनता के बीच सवाल उठ रहा है इतनी सक्षम जांच एजेंसियां आखिर नियम कायदों का पालन न करते हुए जांच को अदालत के पटल पर क्यों रख रही हैं। अदालती कार्यवाही और कानूनी पहलूओं को लेकर कुख्यात घोटालेबाजों को मिली राहत अब गली कूचों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक गलियों में आवाज निकलने लगी है कि बघेल को गिरफ्तारी से बचाने और अपराधों से बचाने के लिये नौकरशाही का एक धड़ा सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। यह सब कुछ प्रभावशील आरोपियों को कानून की गिरफ्त से बचाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। सूत्र यह भी तस्दीक करते हैं कि आबकारी घोटाला या महादेव ऐप घोटाला में लिप्त आरोपियों के बयान सावधानीपूर्वक दर्ज किये जा रहे हैं। इसमें आरोपी सच उगलने और बघेल का नाम तक लेने परहेज कर रहे हैं। घोटालों में लिप्त आरोपियों को बघेल का नाम न लेने की हिदायत देने जाने का मामला भी जांच एजेंसियों के गलियारों में सुर्खियां बटोर रहा है। फिलहाल बघेल की गिरफ्तारी होती या नही इसे लेकर केन्द्र और राज्य सरकार की मंशा भी प्रजातंत्र के तकाजे पर तोली जाने लगी है।

कांग्रेस के कई नेता यहां भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि बघेल बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन गये हैं। पहले अपने पुत्र चैतन्य को बचाने के लिये अब फिर खुद के बचाव में पार्टी की आंखों में धूल झोंकना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेसी नेताओं की आशंका यूं ही नही बनाई जा रही है। वो दावा करने में भी नही चूक रहे हैं कि किसी गोपनीय करार के तहत बघेल ने उत्तर प्रदेश चुनावी प्रभारी रहते हुये करीब 32 ऐसे उम्मीदवारों को कांग्रेस की टिकट दिलवाई थी, जो बीजेपी उम्मीदवारों के सामने बिलकुल टिक नही पाये। नतीजतन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई थी। कांग्रेस गलियारों में मेरठ विधानसभा की सीट पर अर्चना गौतम की उम्मीदवारी का प्रकरण आज भी यूपी के आम कार्यकर्ता नही भूल पाये हैं। बताया जाता है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, फेम बनाकर कांग्रेस नेता के रूप में अर्चना गौतम की ताजपोशी की थी। हालांकि परिणाम पार्टी के सामने रहे। अर्चना गौतम की जमानत जप्त हुई और कांग्रेस चौथे नंबा से भी पीछे खिसक गई। इसके उपरांत बघेल की निगरानी में असम, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। बघेल ने इन राज्यों में जिन इलाकों में प्रचार किया था और जिन कांग्रेसियों को टिकट दिलवाई उनका सूपड़ा साफ हो गया।

बघेल को बताते हैं बीजेपी का स्लीपर सेल

बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता उन्हें का बीजेपी का स्लीपर सेल बताने में भी पीछे नही हैं। उनका दावा है कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग से छुटकारा पाने के लिये बघेल ने कांग्रेस को बीजेपी के हाथों गिरवी रख दिया है। उनके मुताबिक केन्द्रीय स्तर पर बघेल को संरक्षण के चलते बघेल की गिरफ्तारी पर रोक है। छत्तीसगढ़ में सफाई की ओर बढ़ चुकी कांग्रेस को बचाने के लिये प्रदेश में नये नेतृत्व की मांग जोरों पर है। अब कार्यकर्ता महंत जैसे नेताओं के नेतृत्व पर भरोसा जता रहे हैं। जबकि पार्टी के भीतर बघेल को जयचंद की पदवी से नवाजा जा रहा है। इधर बघेल की गिरफ्तारी न होने से बीजेपी संगठन ने भी गहमागहमी देखी जा रही है। विधानसभा के पूर्व बघेल के खिलाफ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने लंबी चौड़ी शिकायतें केन्द्र, राज्य सरकार और जांच एजेंसियों को की थी। यह शिकायतें रंग भी लाई। कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने भी पूर्ववर्ती सरकार के घोटाले का लेखाजोखा मांगा था। लेकिन नौकरशाही के चर्चित धड़े ने आरटीआई के प्रावधानों को भी साथ-साथ में रखकर सूचनाएं प्रदान करने पर भी रोक लगा दी। सरकारी और गैर सरकारी ठिकानों से सबूतों को नष्ट करने का उपक्रम भी शुरू कर दिया।

इस पर रोक लगने से सरकार को अपेक्षित कामयाबी नही मिल पाई। ऐसे संघर्षों के दौर में प्रदेश के कई पत्रकारों ने बघेल सरकार के अपराधों और घोटालों को उजागर करने के लिए एजेंसियों और अदालत के संज्ञान में लाया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता में आने के बावजूद बघेल की गिरफ्तारी को लेकर जारी आंख मिचोली का खेल यूं ही जारी है। बीजेपी के कई नेता स्वीकार्य कर रहे हैं कि कहीं न कहीं बघेल को अनुचित संरक्षण होने से उनकी गिरफ्तारी लगातार टाली जा रही है। मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं जबकि सह आरोपी जेल की हवा खा रहे हैं। प्राप्त खबरों के मुताबिक संगठन के बड़े नेता बघेल की गिरफ्तारी के पक्ष में खड़े हैं। जबकि सरकार में शामिल मुख्यधारा के नेताओं को केन्द्र की हरी झंडी का इंतजार है। उनकी यह भी दलील है कि ऊपर से आदेश मिलते ही बघेल को लेकर धर दबोचा जायेगा लेकिन आदेश तो मिले। ऐसे नेता एजेंसियों को आरोपियों को धड़ पकड़ कानूनी स्वतंत्रता को जायज ठहरा रहे हैं। उनका दावा है कि जांच एजेंसियों को कहीं न कहीं बघेल की गिरफ्तारी की राह तक रहे हैं। उन्हें भी पार्टी के उचित फोरम से बघेल की गिरफ्तारी के स्पष्ट आदेशों का इंतजार है।

विकसित बस्तर की ओर

बस्तर क्षेत्र में कृषक, महिला, युवा उद्यमी और आदिवासी समुदायों के समावेशी विकास के लिए नई रणनीति

कृषि

- किसानों की **आय को दोगुना** करने के लिए विशेष प्रयास
- कृषि उत्पादों की **प्रोसेसिंग ब्रांडिंग** और **मार्केटिंग** को बढ़ावा
- **मिलेट फसलों** की खेती के रकबे का विस्तार
- कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना

पर्यटन

- **बस्तर दशहरा** का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजन
- **धुड़मारास** गांव यूएन की **'बेस्ट टूरिज्म विलेज'** लिस्ट में शामिल
- **बस्तर पर्यटन सर्किट** का विकास
- **पर्यटक गाइड** प्रशिक्षण कार्यक्रम
- **तीरथगढ़ जलप्रपात** पर पारदर्शी पुल के निर्माण की योजना

कौशल उन्नयन

- **90 हजार युवाओं** को कौशल विकास का प्रशिक्षण
- **40 हजार युवाओं** को रोजगार अवसर
- **32 नए कौशल** विकास केन्द्रों की स्थापना
- नई आत्मसमर्पित नक्सली पुनर्वास नीति 2025 में कई विशेष प्रावधान

उद्योग

- नई उद्योग नीति में बस्तर क्षेत्र के युवा उद्यमियों के लिए कई विशेष प्रावधान
- इस्पात उद्योगों के लिए 15 वर्षों तक रॉयल्टी प्रतिपूर्ति का प्रबंध
- आत्म समर्पित नक्सलियों को रोजगार हेतु उद्योगों व संस्थाओं को 5 वर्ष तक उनके वेतन का **40% सब्सिडी** भुगतान

R.O. No. : 13247/ 1

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)